ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

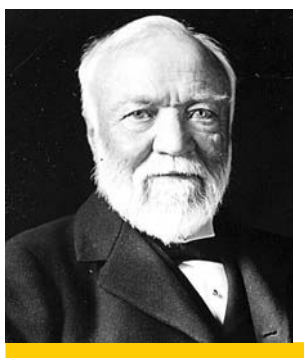

American steel baron comments on...

Travelling on the Indian railways, Carnegie could not help but comment on its impact on Indian society. The introduction of the railways in the country had helped lower caste barriers

Diamonds Need A Makover

The Power of Coffee Blends

यूपी चुनाव से पहले बड़ा ''मास्टर स्ट्रोक'' खेलेगी भाजपा

केन्द्र सरकार 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पूर्व महिला आरक्षण बिल लाने पर गंभीरता से विचार कर रही है

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 मार्च। नरेन्द्र मोदी सरकार संसद के मौजूदा सत्र में महिला आरक्षण विधेयक लाने पर गंभीरता से विचार कर रही है, खासकर 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए।

महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण एक संवैधानिक संशोधन विधेयक है, जो परिसीमन (डिलिमिटेशन) से जुड़ा हुआ है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सरकार इतनी जल्दबाजी में है कि वह इसे परिसीमन से अलग (डिलिंक) करने पर विचार कर रही है और 2011 की जनगणना के आधार पर लगभग 273 सीटें महिलाओं के लिए निर्धारित करने की योजना बना रही है।

परिसीमन के बाद लोकसभा की कुल सीटें बढ़कर 816 होने का अनुमान है।

- चर्चा है कि परिसीमन के बाद लोकसभा की सीटें बढ़कर 816 हो जाएंगी। इनमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। अगर ऐसा होता है तो बड़े पैमाने पर चुनावी गणित प्रभावित हो सकता है।
- महिला आरक्षण बिल संविधान संशोधन बिल है और परिसीमन से जुड़ा हुआ है। सरकार को बिल लाने की इतनी जल्दी है कि वह इसे परिसीमन से ''डीलिंक'' करने पर विचार कर रही है।
- केन्द्रीय गृह मंत्री ने इस पर चर्चा के लिए कुछ विपक्षी दलों के साथ बैठक की, जिसमें ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, तेलुगु देशम व कुछ अन्य क्षेत्रीय दल शामिल थे, पर, कांग्रेस को नहीं बुलाया गया।
- केन्द्र सरकार विधेयक पर सर्वसम्मति चाहती है, जो कांग्रेस के बिना संभव नहीं है। यही नहीं, कांग्रेस के समर्थन के बिना संविधान संशोधन विधेयक भी पारित नहीं हो सकता है।

गृह मंत्री अमित शाह ने आज इस मुद्दे पर चर्चा के लिए कुछ क्षेत्रीय दलों की बैठक बुलाई, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इसमें कांग्रेस को आमंत्रित नहीं किया गया। केवल तेलुगू देशम पार्टी, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और अन्य क्षेत्रीय दलों को बुलाया गया।

संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए दो-तिहाई बहुमत

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'ट्रंप से कोई बात नहीं हुई'

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 मार्च। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के तेहरान के साथ हुई ''उपयोगी बातचीत'' के दावों को सख्ती से खारिज करते हुए ईरान के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई।

ईरानी सरकारी मीडिया ने भी कहा कि देश ने ऐसी कोई बातचीत नहीं की है, जबकि काबुल स्थित ईरानी दूतावास ने ''ईरान की सख्त चेतावनी के बाद ट्रंप की पीछे हटने की कार्रवाही'' शीर्षक से तीखी प्रतिक्रिया पोस्ट की।

- ईरान ने ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया कि उनकी ईरान के नेताओं से युद्ध विराम पर वार्ता हुई है और अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला नहीं करेगा।

जानकार कूटनीतिक सूत्रों का कहना है कि तेहरान ने ट्रंप की चाल को भांप लिया, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति का ढुलमुल रवैया अब जग-जाहिर हो चुका है। हालांकि इस पोस्ट में ट्रंप के इस नाटकीय बयान को पूरी तरह खारिज नहीं किया गया कि दो दिनों से बातचीत चल रही है, लेकिन ईरान की ''फार्स'' समाचार एजेंसी ने एक अज्ञात स्रोत के हवाले से कहा कि अमेरिका के साथ ''कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बातचीत नहीं हो रही है।'

'मैंने पश्चिम एशिया के सभी राष्ट्र प्रमुखों से फोन पर बात की है'

प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में अपने संबोधन में कहा, मैंने सभी से आपस में बातचीत कर तनाव कम करने का आग्रह किया

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 मार्च। वर्तमान संकट को लेकर भारत की संसद से पूरी दुनिया तक एकजुट और सर्वसम्मत संदेश पहुँचे, इस बात के महत्व को बताते हुए, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को स्वीकार किया कि पश्चिम एशिया की स्थिति ''चिंताजनक'' है। उन्होंने भारत की ऊर्जा सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और प्रवासी भारतीयों पर इस युद्ध के व्यापक प्रभाव को रेखांकित किया, साथ ही यह भी कहा कि अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है और अभी तक न तो गर्मियों की फसल बुवाई के मौसम में उर्वरकों की कमी है और न ही कोयले या ईंधन का संकट है।

लोकसभा में अपने संबोधन में मोदी ने कहा, ''पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति चिंताजनक है। यह संकट तीन सप्ताह से अधिक समय से चल रहा है और इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा लोगों के जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। पूरी दुनिया सभी पक्षों से इस संकट को जल्द से जल्द हल करने की अपील कर रही है।''

पिछले महीने शुरू हुआ यह युद्ध हवाई यात्रा से लेकर समुद्री परिवहन और गैस आपूर्ति तक कई क्षेत्रों को प्रभावित कर चुका है। खासकर होर्मुज़ जलडमरूमध्य लगभग बंद होने की स्थिति में है, जिसके जरिए भारत के 40 प्रतिशत कच्चे तेल का आयात और दुनिया के 20 प्रतिशत कच्चे तेल का परिवहन होता है।

ऊर्जा कीमतों पर नजर रख रहे लोगों और घरेलू बजट पर उसके असर को लेकर चिंतित लोगों को भरोसा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- प्रधानमंत्री ने संसद में अपने भाषण में कहा कि पश्चिम एशिया के हालात बेहत चिंताजनक हैं और हम वहाँ रह रहे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास कर रहे हैं।
- मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया के लगभग सभी देशों से हमारे व्यापारिक संबंध हैं। तेल और एलपीजी की हमारी अधिकांश जरुरत यहीं से पूरी होती है, इसलिए इस क्षेत्र में शांति स्थापित होना हमारे लिए बहुत जरुरी है।
- उन्होंने देश की जनता को भरोसा दिलाया कि पैट्रोल, डीज़ल, एलपीजी और खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी।

बंगाल में ''ममता राज'' खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही भाजपा

प्रधानमंत्री मोदी राज्य के 14 स्थानों पर विशाल जनसभा करेंगे

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 मार्च। पश्चिम बंगाल को कथित अराजकता और भ्रष्टाचार से मुक्त कर ''सोनार बांग्ला'' की शुरुआत का वादा करते हुए, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ''संकल्प पत्र'' या घोषणापत्र, जिसे वह 28 मार्च को जारी करने जा रही है, इसमें युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने पर विशेष जोर देने की संभावना है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन राज्य के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां वे बूथ स्तर के प्रबंधन, विधानसभा क्षेत्र की योजना, जिला इकाइयों के बीच समन्वय और जमीनी नेटवर्क को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर पार्टी संगठन को सक्रिय करेंगे। पार्टी के संदेश को मतदाताओं तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने और तयशुदा प्रचार रणनीतियों के जरिए अधिकतम पहुंच सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

- यही नहीं, ममता बनर्जी जिस भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं, वहाँ भी प्र.मंत्री की एक सभा होगी। यहाँ ममता के सामने भाजपा ने सुवेन्दु अधिकारी को उतारा है। कभी ममता बनर्जी के विश्वस्त रहे सुवेन्दु अधिकारी बाद में भाजपा में चले गए थे और 2026 के गत चुनाव में उन्होंने नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी को 1956 वोटों से हराया था।
- भाजपा 28 मार्च को राज्य के लिए चुनाव घोषणा पत्र, ''संकल्प पत्र'' जारी करेगी, जिसमें युवाओं का रोजगार देने पर विशेष फोकस रहने की संभावना है। इसके अलावा कई लोक लुभावन घोषणाएं और विकास के बड़े-बड़े दावे भी घोषणा पत्र में किए जा सकते हैं।

घोषणापत्र में राज्य में शासन व्यवस्था, विकास, रोजगार सृजन, इन्फ्रास्ट्रक्चर, कानून-व्यवस्था, युवा सहभागिता, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण-शहरी संपर्क को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर फोकस रहने की संभावना है।

घोषणापत्र को अंतिम रूप देने के लिए भाजपा ने व्यापक स्तर पर प्रयास किए हैं। राज्य के पार्टी नेताओं ने बुद्धिजीवियों, महिलाओं और युवाओं

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रंप ने कहा, ईरान से वार्ता हो रही है

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 मार्च। घरेलू दबाव, और ईरान के साथ युद्ध के 24वें दिन में प्रवेश करने से खजाने पर बढ़ते आर्थिक बोझ के चलते, अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि अमेरिका की ईरान के साथ अच्छी और उपयोगी बातचीत हुई है और वे ईरानी बिजली संयंत्रों तथा ऊर्जा इन्फ्रास्ट्रक्चर पर किसी भी सैन्य हमले को पांच दिनों के लिए स्थगित करने का आदेश देंगे।

- ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि अमेरिका 5 दिनों तक ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला नहीं करेगा।

लेकिन, ट्रंप ने यह बताने से परहेज किया कि क्या अमेरिका का सहयोगी इज़रायल भी ईरान पर हमले टाल रहा है या नहीं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रंप ने अपनी ''टाको'' छवि को बरकरार रखा

ट्रंप ने अचानक घोषणा की, कि वे ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला नहीं करेंगे, ईरान चाहे होर्मुज़ स्ट्रेट खोले चाहे ना खोले

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 मार्च। राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने अपनी ''टीएसीओ'' (टाको) छवि को बरकरार रखा है। टीएसीओ अर्थात ''ट्रंप ऑलवेज़ चिकन्स आउट।'' इसका अर्थ है, ट्रंप हमेशा पीछे हट जाते हैं। इस छवि के अनुरुप ट्रंप ने अचानक यह घोषणा कर दी कि वे ईरान के नागरिक बिजली संयंत्रों पर हमला नहीं करेंगे, भले ही होर्मुज़ जलडमरुमध्य (स्ट्रेट) से जहाजों की आवाजाही सामान्य न हो।

पिछले सप्ताह ट्रंप ने कहा था कि यदि ईरान ने सोमवार शाम तक होर्मुज़ स्ट्रेट से नियंत्रण नहीं हटाया और जहाजों को निर्बाध आवाजाही की अनुमति नहीं दी, तो वे ईरान की सभी बिजली उत्पादन इकाइयों को नष्ट कर देंगे।

इसके जवाब में ईरान ने धमकी दी थी कि वह क्षेत्र के अरब देशों में सभी बिजली संयंत्रों, अन्य बुनियादी ढांचों और विशेष रूप से समुद्री पानी को मीठा कर पीने योग्य बनाने वाले डी सैलाइनेशन प्लांट्स के साथ ही, अमेरिका से जुड़े सभी ठिकानों और इकाइयों को निशाना बनाएगा।

कई लोग ट्रंप के इस अचानक पीछे हटने को पहले दौर में ईरान की जीत के रूप में देख रहे हैं, हालांकि यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि आगे क्या होगा।

- जबकि, गत सप्ताह ट्रंप ने घोषणा की थी, अगर ईरान ने होर्मुज़ स्ट्रेट नहीं खोला और जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित नहीं की तो वे ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले करेंगे।
- इसके जवाब में ईरान ने भी धमकी दी थी कि वह खाड़ी देशों के डीसैलिनेशन प्लांट्स (समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य बनाने वाला संयंत्र) और इन क्षेत्रों में मौजूद अमेरिकन इकाइयों पर भारी हमला करेगा।
- ईरान का कहना है कि इन्हीं धमकियों के कारण ट्रंप पीछे हटे हैं, लेकिन असल में ट्रंप पहले भी ऐसा करते रहे हैं। वे जोर-शोर से कोई मुहिम शुरु करते हैं और घबराकर पीछे हट जाते हैं, यूक्रेन में भी उन्होंने ऐसा ही किया था।
- घबराकर पीछे हटने के कारण ही ट्रंप की टाको (टीएसीओ) इमेज बन गई है अर्थात् ''ट्रंप ऑलवेज़ चिकन्स आउट।''

ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका की ईरानी अधिकारियों के साथ बहुत उपयोगी बातचीत हुई है, जिससे अमेरिका-इज़रायल और ईरान के बीच सभी मुद्दों के समग्र समाधान की दिशा में सकारात्मक परिणाम मिले हैं।

लेकिन, ईरान के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने ट्रंप के इन दावों को तुरंत खारिज करते हुए कहा कि दोनों पक्षों के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ है। इसके बजाय, ईरान का कहना है कि उसके जवाबी हमले की धमकियों ने ही अमेरिका को अपनी योजना को आगे बढ़ाने से रोक दिया।

क्षेत्र के रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पश्चिम एशिया में अमेरिका के सहयोगी देशों के भारी दबाव के कारण अमेरिका को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना पड़ा। अब तक सऊदी अरब, कतर, यूएई, ओमान और बहरीन

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट ने बाबूलाल कटारा की अंतरिम जमानत रद्द की

जयपुर, 23 मार्च। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती-2022 पेपरलीक मामले में आरपीएससी के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा को मिली अंतरिम जमानत को रद्द कर दिया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस

- राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि कटारा ने अदालत से तथ्य छुपाये हैं। उसके खिलाफ पांच अपराधिक मामले लंबित हैं तथा उसके पास से 51 लाख रूपए नकद व 500 ग्राम सोने के आभूषण बरामद हुए थे।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'अगर अमेरिका ने हमला किया तो पाकिस्तान दिल्ली-मुंबई को निशाना बनाएगा'

भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित का यह बयान क्या सिर्फ नारेबाजी है या पाक ऐसी टिप्पणियों के जरिए खुद को बचाने का जतन कर रहा है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 मार्च। भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित की यह टिप्पणी, कि यदि अमेरिका हमला करता है तो पाकिस्तान दिल्ली और मुंबई को निशाना बना सकता है, पहली नज़र में चौंकाने वाली लगती है। लेकिन दक्षिण एशियाई भू-राजनीति की भाषा में यह किसी वास्तविक सैन्य खतरे से ज्यादा एक परिचित रणनीतिक संकेत (स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग) का साधन है, जिसका उद्देश्य जोखिम को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाना, संघर्ष के दायरे को व्यापक करना और एक साथ कई पक्षों की गणनाओं को प्रभावित करना होता है।

- रणनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह के बयानों का उद्देश्य यह होता है कि जोखिम को इतना बढ़ा-बढ़ाकर पेश किया जाए कि उससे संभावित हमले से बचाव हो सके। यहाँ पाकिस्तान को खतरा अमेरिका से है, क्योंकि अमेरिका में एक वर्ग पाकिस्तान को ईरान की तरह परमाणु खतरा बता रहा है।
- वैसे बासित अभी किसी पद पर नहीं है और भारतीय नीतिकार अधिकारिक नीति व पूर्व डिप्लोमैट्स के बयानों को अलग तरह से देखते हैं, क्योंकि पूर्व अफसर नीति संबंधी वो बाते भी कह देते हैं, जिन्हें कहने से मौजूदा अधिकारी बचते हैं, इसलिए बासित के बयान को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ भी नहीं किया जा सकता है।
- पाकिस्तान द्वारा दिल्ली और मुंबई का उल्लेख स्पष्ट संकेत देता है कि अगर अमेरिका, पाकिस्तान पर हमला करता है तो वह उस संघर्ष को सीमा पार, यानि भारत तक विस्तार दे सकता है।
- पर, अभी भारत के लिए जरूरी है कि जवाबी बयानबाजी में न उलझे और पूर्ण सतर्कता बरतते हुए तैयारी में जुटा रहे, ताकि हर खतरे का मुकाबला किया जा सके।

सबसे पहले, बासित अब पद पर नहीं हैं। यह बात महत्वपूर्ण है। भारतीय सुरक्षा योजनाकार आमतौर पर आधिकारिक नीति और पूर्व राजनयिकों के बयानों में फर्क करते हैं, क्योंकि पूर्व अधिकारी अक्सर वह स्पष्टता दिखाते हैं, जिससे वर्तमान अधिकारी बचते हैं। इसलिए उनके बयान में नीतिगत तत्व तो नहीं है, लेकिन इसे पूरी तरह नज़रअंदाज़ भी नहीं किया जाता। ऐसे क्षेत्र में, जहां संकट अप्रत्याशित रूप से बढ़ सकते हैं, बयानों को भी गहराई से पढ़ा जाता है, ताकि रणनीतिक सोच का अंदाजा लगाया जा सके।

एक स्तर पर, यह बयान पाकिस्तान की उस पुरानी रणनीति के अनुरूप है, जिसमें वह तनाव को बढ़ाकर निरोध (डिटरेंस) स्थापित करने की कोशिश करता है। दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों का उल्लेख स्पष्ट संकेत देता है कि पाकिस्तान से जुड़ा कोई भी संघर्ष, चाहे वह अमेरिका द्वारा शुरू किया गया हो या नहीं, भौगोलिक या राजनीतिक रूप से सीमित नहीं रहेगा। इन शहरों का

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दो और भारतीय जहाजों ने होर्मुज़ पार किया

नई दिल्ली, 23 मार्च। भारत के दो और जहाज होर्मुज स्ट्रेट को पार कर गए हैं। इन जहाजों में एलपीजी है और इनके दो से ढ ाई दिन में भारत पहुंचने की उम्मीद है। जानकारी के मुताबिक, पाइन गैस और जग वसंत होर्मुज स्ट्रेट को पार कर चुके हैं। दोनों जहाज सोमवार सुबह फारस की खाड़ी से रवाना हुए थे। दोनों जहाज एक-दूसरे के करीब चल रहे हैं। शिपिंग मिनिस्ट्री के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि दोनों जहाजों पर लगभग 92,000 टन एलपीजी है। उन्होंने बताया कि खाड़ी से भारत तक पहुंचने में जहाज को आमतौर पर दो से ढ ाई दिन लगते हैं।

- 92,000 टन एलपीजी लेकर आ रहे ये जहाज दो-ढाई दिन में भारत पहुंच जाएंगे।

जहाज ट्रैकिंग आंकड़ों से पता चलता है कि होर्मुज स्ट्रेट को पार करने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)